

मुख्य समाचार

- प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले में विपक्ष ने सदन से किया वाकआउट—मुख्यमंत्री ने कहा—सरकार मामले की निष्पक्ष जांच करेगी।
- प्रदेश के 2025—26 के बजट पर चर्चा के दौरान भाजपा ने राजस्व घाटे के लिए सरकार को ठहराया दोषी।
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की भेंट—प्रदेश हित के मुद्दों पर की चर्चा।
- राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने पांगी घाटी के चैहणी जोत में सुरंग निर्माण की केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मांग।

वाकआउट

हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक व चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में आज विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज विपक्षी दल भाजपा ने इस घटना की सीबीआई जांच की मांग को लेकर पहले सदन में हंगामा किया और बाद में सदन से वाकआउट भी किया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर नियम-67 के तहत स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने नामंजूर कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कहा कि सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच करेगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता.....

प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक व चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में सीबीआई जांच को लेकर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया और फिर सदन से वाकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रश्नकाल के दौरान विमल नेगी की मौत का मामला उठते हुए कहा कि सरकार को इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं और पावर कॉरपोरेशन की कार्यप्रणाली पहले दिन से ही विवादों के घेरे में है।

सदन में विपक्ष द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और उचित कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से मृतक विमल नेगी की पत्नी संतुष्ट है और उन्होंने स्वयं व्यक्तिगत तौर पर उनसे बात की है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर इस सारे मामले पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया।

सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया और नारेबाजी करते हुए पूरा विपक्ष सदन से बाहर चला गया। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने व्यवस्था देते हुए कहा कि उन्हें विमल नेगी की मौत के मामले में भाजपा के जयराम ठाकुर, डॉ. जनकराज, रणधीर शर्मा, विपिन सिंह परमार, सुधीर शर्मा और अन्य की ओर से नियम-67 के तहत स्थगन प्रस्ताव आज ही प्राप्त हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने इस मामले में पहले ही अपेक्षित कार्रवाई कर दी है। ऐसे में इस मामले को नियम-67 के तहत उठाने का अब कोई औचित्य नहीं है। रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार शिमला।

अंतिम संस्कार

इस बीच प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी का आज उनके पैतृक गांव कटगांव में अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर हजारों लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। प्रशासन की ओर से किन्नौर के उपायुक्त अमित कुमार शर्मा भी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। इस

दौरान मौजूद लोगों ने राज्य सरकार से विमल नेगी की मौत के मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग भी की। गौरतलब है कि विमल नेगी बीते 10 मार्च को लापता हो गए थे और 19 मार्च को उनका शव गोविंद सागर झील से बरामद हुआ था।

प्रश्नकाल

स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि 2 सौ डॉक्टरों के पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है और इसके लिए बीते 16 मार्च को परीक्षा आयोजित की गई। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक संजय अवस्थी के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने ये बात कही। विधायक चंद्र शेखर के सवाल के जवाब में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि एचपी शिवा परियोजना की कुल लागत एक हजार 2 सौ 92 करोड़ रुपए है जिसका 80 प्रतिशत वित्तपोषण एशियन विकास बैंक द्वारा जबकि शेष 20 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाना है।

बजट चर्चा

प्रदेश विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के बजट पर जारी चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने 6 हजार 3 सौ 90 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य में निवेश नहीं बढ़ेगा, तब तक यह घाटा बढ़ता रहेगा। विपिन परमार ने कहा कि राज्य सकल घरेलू उत्पादन के 3 फीसदी से अधिक कर्ज लेने के कारण राज्य की कैपिंग की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश को 9 हजार 3 सौ आवास आवंटित करने के अलावा प्राकृतिक आपदा के समय मनरेगा के तहत एक हजार एक सौ करोड़ रुपए की मदद की गई है। इसके अलावा केंद्रीय करों में हिस्सेदारी को 32 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी किया गया है। विपिन परमार ने कहा कि वर्ष 2025-26 में प्रदेश को 11 हजार 8 सौ 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिकी में फार्मा हब का योगदान 12 फीसदी है, जिस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने टांडा में कैथ लैब को लेकर भी सवाल उठाए। कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह बाली ने टांडा में कैथ लैब बंद होने की बात को नकारा। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय जी.एस.टी. अनुदान के 16 हजार करोड़ रुपए मिले। इसके अलावा उनके कार्यकाल में राजस्व घाटा अनुदान राशि भी बढ़ी हुई मिली।

निधन

पूर्व मंत्री केवल सिंह पठानिया का आज निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। वे कांगड़ा जिले के नूरपुर क्षेत्र से संबंध रखते थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में कहा कि ये सदन केवल सिंह पठानिया के निधन पर शोक प्रकट करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल सिंह पठानिया वर्ष 1972, 1990 और 1993 में प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। वे राज्य सरकार में 1995 से 1998 तक परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश व समाज के लिए दिए गए उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, कृषि मंत्री चन्द्र कुमार और विधायक रणधीर सिंह, भवानी सिंह पठानिया और संजय रतन ने भी पूर्व मंत्री केवल सिंह पठानिया के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सभी सदस्यों ने उनके निधन पर दो मिनट का मौन रखा।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। उन्होंने वित्त मंत्री से हिमाचल प्रदेश पर व्यय विभाग द्वारा बाह्य सहायता प्राप्त करने के लिए लगाई गई सीमा की समीक्षा करने का अनुरोध किया और पूर्व की स्थिति को बहाल करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने राजस्व घाटा अनुदान को कम करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने

अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कई कदम उठाए हैं, हालांकि यह कदम वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए बजटीय दायित्वों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य को 2025–26 के लिए जी.एस.डी.पी. का 2 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति देने का आग्रह भी किया। केन्द्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज शिमला के चौड़ा मैदान में हिमाचल प्रदेश किसान सभा के प्रतिनिधिमंडल से बात की। इस अवसर पर किसान सभा की ओर से पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

सिकंदर

राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की और पांगी घाटी के चैहणी जोत में सुरंग निर्माण को लेकर चर्चा कर उन्हें एक मांग पत्र सौंपा। सिकंदर कुमार ने कहा कि संर्दियों में लोगों को पांगी घाटी पहुंचने के लिए लगभग 15 हजार फुट ऊंचे साच-पास से होकर आना पड़ता है। उन्होंने कहा कि चैहणी जोत में सुरंग बनने से लोगों को सुविधा मिलेगी और वे साल भर चम्बा मुख्यालय से जुड़े रहेंगे। केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस कार्य के लिए केन्द्र की तरफ से उन्हें हर सम्भव सहायता का आश्वासन दिया।

जगत सिंह नेगी

राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि राज्य सरकार 2005 से पहले वनभूमि पर आश्रित जनजातीय व प्रदेश के अन्य लोगों को 50 बीघा तक की जमीन का मालिकाना हक देगी। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में वनअधिकार अधिनियम को लागू करने जा रही है जिससे सदियों से वनभूमि पर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को भूमि का मालिकाना हक मिल सके।

मुख्य समाचार एक बार फिर

- प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले में विपक्ष ने सदन से किया वाकआउट—मुख्यमंत्री ने कहा—सरकार मामले की निष्पक्ष जांच करेगी।
- प्रदेश के 2025–26 के बजट पर चर्चा के दौरान भाजपा ने राजस्व घाटे के लिए सरकार को ठहराया दोषी।
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की भेंट—प्रदेश हित के मुद्दों पर की चर्चा।
- राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने पांगी घाटी के चैहणी जोत में सुरंग निर्माण की केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मांग।